Swatantrata Sainik Samman Pension for Freedom Fighters of Karnataka

1047. SHRT H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of freedom fighters who have applied for Swatantrata Sainik Samman Pension from Karnataka, District-wise during the last three years;

(b) what is the number of sanctioned and rejected cases respectively; and

(c) by when the remaining applicants are likely to be sanctioned the penaion?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED): (a) to (c) A total number of 18,230 applications had been received from Karnataka State under the Freedom Fighters Pension Scheme. Out of these, pension has been sanctioned in 9675 cases as on 31-1-1990. 4 casas relating to "Arya Samaj" Movemennt of 1938-39 are pending consideration by the Non-Official Committee as on 31-1-1990. The remainng cases have not been found eligible for grant of pension under the Provisions of the Central Pension Scheme. The District-wise information in this regard is *not,* however, maintained.

देश में टेलीफोन कनेक्शन

1048. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है तथा प्रत्येक राज्य की प्रतीक्षा सूची क्या है तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने मे कितना समय लगने की संभावना है तथा इस प्रयोजनार्थ तैयार किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) टेलीफोन उपकरणों तथा संबंधित पुर्जों के निर्माण के संबंध में स्थिति क्या है तथा उनकी मांग और आपूर्ति का अनुपात कितना है तथा इस संबंध में स्थिति में कब तक सुधार होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री, साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) उत्तर संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) टेलीफोन उपकरणों एवं अतिरिक्त पुर्जों का विनिर्माण मैसर्स आई० टी०आई० के अलावा अनेक कंपनियों द्वारा भी किया जा रहा है । विभाग की मांग की तुलना में टेलीफोन उपकरणों एवं अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति संतोषजनक है ।

क्र० सं०	राज्य	31-1-1990 की स्थिति के अनुसार चालू कनेक्शन	31-1-90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	आन्ध्र प्रदेश	299801	76290
2.	असम	37129	11420
3.	बिहार	92498	17478
4.	गुजरात	407110	128613
5.	हरियाणा	83679	46421

क्र० सं०	राज्य	31-1-90 की स्थिति के अनुसार चालू कनेक्शन	31-1-90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
6.	हिमाचल प्रदेश	27983	7503
7.	जम्मू-कश्मीर	27233	15720 (31-12-89)
8.	कर्नाटक	284060	90096
9.	केरल, पांडिचेरी एवं लक्षद्वीप सहित	217306	147377
10.	मध्य प्रदेश	158415	74803
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	859608	393909
12.	उड़ीसा	56345	7345
13.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	179087	122045
14.	राजस्थान	133135	84059
15.	तमिलनाडु	415450	127679
16.	उत्तर प्रदेश	276762	83098
17.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	298388	38575
18.	अरुणाचल प्रदेश	2660	359
19.	मणिपुर	4029	1526
20.	मेघालय	6248	1233
21.	मिजोरम	1966	467
22.	नागालैंड	3795	927
23.	त्रिपुरा	4188	868
24.	संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली	439732	261413

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार नेटवर्क का 50 लाख और अधिक लाइनों द्वारा विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। उद्देश्य इस प्रकार है :—

(क) 5000 लाइनों तक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन प्रदान करना।

(ख) 5000 या इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंजों में औसतन लगभग एक वर्ष तक प्रतीक्षा सूची रखना। सूची में दर्ज मौजूदा व्यक्तियों को उत्तरोत्तर टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे। तथापि, यह व्यवस्था सरकार द्वारा योजना को मंजूरी देने तथा उपस्कर के समय पर उपलब्ध होने की स्थिति पर निर्भर करेगी।